RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह
रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.
फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 337 | दि. 08-04-2019 सोमवार | वि.सं. 2075 | चैत्र सुद-०३ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान

पाकिस्तान को डर, १६ से २० अप्रैल के बीच फिर हमला कर सकता है भारत

हमारे पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी

(संपूर्ण समाचार सेवा) कराची, एयर स्ट्राइक के खौफ से पाकिस्तान अब भी उबर नहीं पाया है। उसने बेहद विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है कि भारत इस महीने एक और हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को यह बात कही। दरअसल, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों परमाणु देशों के बीच टेंशन है। कुरैशी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से यह हमला १६ से २० अप्रैल के बीच हो सकता है। पाकिस्तान में खौफ कितना है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इंडियन एयर फोर्स की स्ट्राइक के एक महीने बाद भी पड़ोसी देश ने हवाई मार्ग पूरी तरह से नहीं खोले हैं। स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान ने भारत से आने-जाने वाली उड़ानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने दो दिन पहले पश्चिमी देशों की ओर जाने वाली फ्लाइटों के लिए अपने एक हवाई रास्ते को खोला जबकि बाकी बचे १० हवाई रास्ते अब भी बंद रहेंगे। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने १४ फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें सेना के ४० जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए २७ फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान के फाइटर जेट को खदेड़ने के दौरान पाक एयर फोर्स ने एक भारतीय विमान को गिरा दिया था और उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन भारत की तरफ से पड़े दबाव के चलते पाकिस्तान को भारतीय पायलट को रिहा करना पड़ा था। कुरैशी ने मुल्तान में पत्रकारों से कहा, हमारे पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक यह हमला १६ से २० अप्रैल के बीच किया जा सकता है। हालांकि कुरैशी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उन्होंने किस आधार पर इस टाइमिंग की बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश के साथ इसकी जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय को इस संबंध में ईमेल से पूछे गए सवाल के जवाब में अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की त्रिपुरा में रैली

मिडिल क्लास पर अब ज्यादा टैक्स लगाकर बदला लेना चाहती है कांग्रेस

कांग्रेस और लेफ्ट दल त्रिपुरा और केरल में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में उन्हें (मोदी को) गाली देने के लिए एक हो जाते हैं : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को त्रिपुरा में रैली की। उदयपुर में हुई इस जनसभा में मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमला बोला। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर मध्यम वर्ग को सजा देने का मन बना चुके हैं, जिनसे लोगों को बचकर रहना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दल त्रिपुरा और केरल में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में उन्हें (मोदी को) गाली देने के लिए एक हो जाते हैं। रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मोदी ने उसे ढकोसला पत्र बताया। मोदी ने कहा कि ५०-६० पेज के उस घोषणा पत्र में एक बार भी मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं है। मोदी बोले कि मध्यम वर्ग ने मिलकर बीजेपी की सरकार बनवाई थी इसलिए अब कांग्रेस और बाकी दल मिलकर मिडिल क्लास को सजा देना चाहते हैं। मोदी ने इशारों-इशारों में कहा कि कांग्रेस सरकार जो न्याय योजना लानेवाली है उसके लिए पैसा मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाकर निकाला जाएगा। मोदी ने कहा, कांग्रेस समेत कुछ दल मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगाने की कोशिश में है। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा करके लाइसेंस राज फिर से लाया जाएगा। इससे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग को खत्म कर दोगे तो देश का भला कैसे होगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने आगे कहा कि चौकीदार को हराने के लिए नामदार (राहुल गांधी) भारत के टुकड़े करने की इच्छा रखनेवालों का भी साथ दे रहे हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लेफ्ट पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं लेफ्ट पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि लेफ्ट पार्टी के लिए अपना संविधान देश के संविधान से भी ऊपर है। मोदी बोले, पहले जिनके दर्जनों सांसद होते थे, वे आज हांफ रहे हैं। पहले इनके नेता जमीन पर राजनीति करते थे और अब सिर्फ टीवी स्टूडियो में नजर आते हैं। मोदी ने कहा कि लेफ्ट के नेता देश की दशा ठीक करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते बल्कि अपनी दशा सुधारना चाहते हैं।

रोड शो से शक्तिप्रदर्शन फिर विश्वनाथ का दर्शन

मोदी २६ अप्रैल को वाराणसी में चुनाव के लिए नामांकन करेंगे

नामांकन के दौरान अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, गडकरी भी मौजूद रहेंगे

(संपूर्ण समाचार सेवा) वाराणसी, पीएम नरेन्द्र मोदी २६ अप्रैल को वाराणसी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज सहित बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि २०१४ के तर्ज पर ही इस बार भी पीएम मोदी नामांकन से पहले २५ अप्रैल को लंका से दशाश्वमेध घाट तक करीब १० किलोमीटर लंबा रोड शो करके शक्तिप्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी २६ अप्रैल को बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नामांकन के लिए जाएंगे। बता दें कि वर्ष २०१४ के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी आने के बाद मलदहिया से कचहरी इलाके तक विशाल रोड शो करने के बाद नामांकन किया था। बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पिछले दिनों बताया था कि छह अप्रैल से मोदी का चुनावी कार्यालय काम करने लगेगा। बताया जा रहा है कि रोड शो के जरिए पीएम मोदी वाराणसी से ही पूरे पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश करेंगे। धर्म नगरी काशी एक बार फिर यूपी के सियासी तापमान का बैरोमीटर बनने को तैयार है। गंगा की शांत धारा के किनारे सियासी लहरें उफान मारेंगी। यहां की लोकसभा सीट पर हर चुनाव हमेशा ही खास रहा है। कभी यह सीट प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती रही तो अब आरएसएस की गहरी पैठ के चलते भगवा ब्रिगेड का मजबूत किला बनी है। बनारस में शुरुआती तीन चुनाव को छोड़ दें तो १९८४ से अब तक के तीन दशक से ज्यादा समय में कांग्रेस सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज करा सकी है। १९९१ से लेकर अब तक सिर्फ २००४ के चुनाव को छोड़ भगवा परचम ही लहरा रहा है। इसे चुनावी टोटका कहें या फिर संयोग, हैट्रिक लगाने वाले कांग्रेस के बाबू रघुनाथ सिंह और बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल को जनता ने चौथी बार संसद पहुंचने का मौका नहीं दिया। २०१४ के तर्ज पर ही इस बार भी पीएम मोदी नामांकन से पहले २५ अप्रैल को लंका से दशाश्वमेध घाट तक करीब १० किलोमीटर लंबा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी २६ अप्रैल को बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नामांकन के लिए जाएंगे। बता दें कि वर्ष २०१४ के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी आने के बाद मलदहिया से कचहरी इलाके तक विशाल रोड शो करने के बाद नामांकन किया था। बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पिछले दिनों बताया था कि छह अप्रैल से मोदी का चुनावी कार्यालय काम करने लगेगा। बताया जा रहा है कि रोड शो के जरिए पीएम मोदी वाराणसी से ही पूरे पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश करेंगे। काशी में वर्ष २०१४ का चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। कारण गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में सक्रिय हुए नरेन्द्र मोदी चुनाव मैदान में थे।

महागठबंधन की महारैली में बोलीं मायावती

देवबंद : भीड़ देखकर पगला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मुसलमानों से अपील की कि कांग्रेस के झांसे में न आएं और बीजेपी को हराने गठबंधन को वोट दें : मायावती

(संपूर्ण समाचार सेवा) देवबंद, यूपी के देवबंद में बहुजन समाज पार्टी, समजावादी पार्टी और लोकदल की पहली संयुक्त रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वेस्ट यूपी के मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस के झांसे में न आएं और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। बीएसपी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि महागठबंधन की महारैली में उमड़ी भीड़ के बारे में जब पीएम मोदी को जानकारी मिलेगी तो वह घबराकर पगला जाएंगे और सराब-सराब करने लगेंगे। बीएसपी नेता ने कहा कि अगर चुनाव या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई तो गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा, बीजेपी के छोटे-बड़े चौकीदार कुछ भी कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे दिन का वादा कर मोदी ने लोगों को गुमराह किया और सरकारी खजाने को लुटा दिया। बिना तैयारी के नोटबंदी और जीएसटी लागू करने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। बीजेपी के शासन में आरक्षण व्यवस्था कमजोर हुई है। बीजेपी पूंजीपतियों को धनवान बनाने में जुटी रही। मायावती ने कहा कि बीजेपी जा रही है, महागठबंधन आ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए कर रही है। चुनाव में किए गए वादे का एक चौथाई काम भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसी भी राज्य में किसानों का बकाया नहीं रहेगा। मायावती ने कहा कि पहले की कांग्रेस की सरकार की तरह ही बीजेपी सरकार के वादे खोखले ही रहे हैं। मायावती ने कहा, मोदी की देशभक्ति सामने आ गई है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार से रक्षा सौदे तक अछूते नहीं। चौकीदारी की नाटकबाजी भी बीजेपी को नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का १५ लाख रुपये का का वादा मजाक बनकर रह गया। मायावती ने पश्चिम यूपी के मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे कांग्रेस की बजाय गठबंधन को वोट दें। गठबंधन ही बीजेपी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस पार्टी यह मानकर चल रही है कि हम जीते या न जीतें गठबंधन के प्रत्याशी नहीं जीत नहीं पाएं। इसलिए वह ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही है जिससे गठबंधन को नुकसान हो। कांग्रेस ने सहारनपुर में इमरान मसूद को टिकट देकर मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश की है। बीएसपी नेता ने कहा कि बीजेपी को यूपी में हार का मुंह दिखाना है तो मुस्लिम समाज को गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देना होगा।

मोदी, शाह और हेमामालिनी हैं राजस्थान में स्टार प्रचारक

(संपूर्ण समाचार सेवा)जयपुर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान लोकसभा चुनावों के लिए रविवार को जारी ४० स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, बालीवुड अभिनेत्री हेमामालिनी सहित केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गड़करी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार स्टार प्रचारकों की सूची में सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रकाश जावडेकर, अर्जुनराम मेघवाल, सी.आर. चौधरी, पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद डॉ किरोडी लाल मीणा सहित राज्य के कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में चुनाव दो चरणों में होना है। पहले चरण में १३ सीटों के लिए २९ अप्रैल को और दूसरे चरण के १२ सीटों के लिये ६ मई को मतदान होना है।

संपादकिय

AFSPA पर छिड़ी बहस, चुनाव के दौरान ही कांग्रेस को क्यों दिखी AFSPA में खामी?

यह ठीक नहीं कि चुनाव के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे गंभीर मसलों पर भी राजनीतिक दल आरोप–प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस और भाजपा के बीच सशस्त्र बलों संबंधी अधिनियम यानी अफस्पा को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उससे बचा जाना चाहिए था। यह बयानबाजी इसीलिए शुरू हुई, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो इस कानून की समीक्षा करेगी और कुछ मामलों में सुरक्षा बलों को इस कानूनी कवच से बाहर किया जाएगा। समझना कठिन है कि कांग्रेस को अफस्पा में खामी अभी ही क्यों दिखी ? आखिर दस साल तक सत्ता में रहने के दौरान उसे इस कानून में कोई खामी क्यों नहीं दिखी या फिर वह यह कहना चाह रही है कि बीते पांच सालों में ऐसा कुछ हुआ है जिससे इस कानून में संशोधन–परिवर्तन आवश्यक हो गया है ? अफस्पा आज का कानून नहीं है। इसे 1958 में तब बनाया गया था जब कांग्रेस के सामने विपक्ष की कहीं कोई गिनती नहीं होती थी। समस्या यह नहीं है कि कांग्रेस ने अफस्पा की समीक्षा की बात की। समस्या यह है कि वह यह कह रही है कि लोगों के लापता होने और प्रताडना एवं यौन हिंसा के मामलों में सुरक्षा बलों को अफस्पा के दायरे से बाहर किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस यह मान रही है कि सुरक्षा बल लोगों को प्रताडित करते हैं या फिर यौन हिंसा में लिप्त रहते हैं ? क्या वह इस नतीजे पर उन आरोपों के आधार पर पहुंची है जो सुरक्षा बलों पर कभी–कभार लगते हैं ? कम से कम कांग्रेस के नेताओं को तो यह अच्छे से पता होना चाहिए कि अक्सर इस तरह के आरोप सुरक्षा बलों को बदनाम करने और उनका मनोबल प्रभावित करने के लिए लगाए जाते है कहीं कांग्रेस उन मानवाधिकारवादियों से तो प्रभावित नहीं जो कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती को मुद्दा बनाते रहते हैं ? यह वही मानवाधिकारवादी हैं जो घाटी में पत्थरबाजों के गिरोहों और उन्हें मिल रहे राजनीतिक संरक्षण पर कुछ नहीं कहते। इस पर हैरत नहीं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अफस्पा की समीक्षा के वादे का घाटी के नेताओं ने स्वागत किया। अच्छा होता कि कांग्रेस केवल यहीं तक सीमित रहती कि वह सत्ता में आने पर अफस्पा की समीक्षा करेगी। किसी भी कानून की समीक्षा करने में हर्ज नहीं। सच तो यह है कि समय के साथ पुराने कानूनों की समीक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि अफस्पा जैसे कानूनों की समीक्षा चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता। इसी के साथ यह भी ध्यान रहे कि अगर सेना को अशांत क्षेत्रों में तैनात करना है तो उसे कुछ विशेष अधिकार देने ही होंगे। ये अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर सैन्य अधिकारियों के दृष्टिकोण को सबसे अधिक महत्व देना होगा। यह अजीब है कि कांग्रेस ने कुछ खास मामलों को अफस्पा से बाहर करने की बात तो कह दी, लेकिन इस बारे में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी डीएस हुड्डा की राय लेना जरूरी नहीं समझा जिन्होंने उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक विस्तृत दृष्टिकोण पत्र तैयार किया था।

कैग जैसी संस्था को संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की

(जी.एन.एस.) जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपने राफेल राग पर लगाम लगाएंगे तब उन्होंने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा उछाला। इतना ही नहीं उन्होंने तथ्यों से मुंह चुराते हुए इस सौदे में देरी का आरोप भी मोदी सरकार पर म ? दिया, जबकि हर कोई जानता है कि मनमोहन सरकार कैसे वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली मारे बैठी रही। आखिर राहुल का रवैया खुद को जबरन सही साबित करने वाला नहीं तो और क्या है? यह तो कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है। राफेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय को हिकारत भरी नजरों से देखना भला और क्या है ? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने यही सब तो किया था! 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी में यह प्रवृत्ति बलवती होने लगी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवाद की ओर बड रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा तो आपातकाल से पहले ही दे दिया गया था। इस नारे को कांग्रेसी सांसद शशि भूषण ने उछाला था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसका कभी विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यहां तो सिर्फ दोहरे मापदंड की बात हो रही है। इस पृष्ठभूमि में यह बताना प्रासंगिक है कि कैग जैसी संस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की और साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री ने किस तरह उसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल खडा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। सरकार के अफसर तो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं, पर कांग्रेस की मौजूदा पीडी ने राजनीतिक कारणों से संस्था के प्रति जवाहरलाल नेहरू की भावना की भी परवाह नहीं की। उसे तो बस यही चाहिए कि कोई संस्था उस व्यक्ति को राफेल मामले में दोषी ठहरा दे जिसको कांग्रेस दोषी देखना चाहती है। तभी उसे कांग्रेस के उस प्रथम परिवार के समकक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री को ला देने में सुविधा होगी। याद रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैग की रिपोर्ट के बाद अच्छा होता कि राहुल राफेल पर दोबारा चर्चा करने से बचते। बहरहाल आपातकाल तथा अन्य अनेक कारणों से इंदिरा गांधी की 1977 के चुनाव में पराजय हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तब लगा था कि कांग्रेस की इमरजेंसी की मानसिकता का खात्मा हो गया, पर कांग्रेस की नई पीडी तो उसे बनाए रखने के पक्ष में लगती है!

कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग

(जी.एन.एस.) आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारणों में से एक है। यह बात शत–प्रतिशत सही है कि हमने जिस तरह की जीवनशैली अपना रखी है वह एक दिन हम सबको डुबो देगी या फिर हमारा दम घोंट देगी। अगर हम मात्र जीवन की कुछ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित होते तो भी चलता, पर अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही है। दुर्भाग्य यह है कि हम इस बदलते हालात की चर्चा तो कर रहे हैं, पर इन सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हर मौसम के बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं मिली थी ? जॉन टेंडल ने वर्ष 1850 में यह बता दिया था कि ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या ठंडी का कारण बन सकती हैं। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमशः 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं जो कार्बन उत्सर्जन के खतरे को कम कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने उपयोगों के लिए भयानक रूप से जंगलों का हनन किया है। वर्ष 2017 में अकेले 390 लाख एकड वनों की कटाई हुई। मतलब एक मिनट में एक पेड काटा गया। यह कटाई हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है जिसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। मसलन टिंबर के लिए 37 फीसद वनों का हनन होता है, वहीं खेती के लिए 28 फीसद, सडक निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में करीब 140 फीसद। इसके अतिरिक्त 21 फीसद वन दावानल की भेंट चड जाते हैं। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मीट और मीट उत्पाद से जुडी हमारी खाद्य आदतें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बडा कारण हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि इनके लिए वर्ष 2030 में आज के मुकाबले 67 फीसद ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग होगा। मतलब साफ है आने वाले दिनों में ये इंसानों में संक्रमण का एक बडा कारण बनेंगे। एक आकलन है कि वर्ष 2050 तक सालाना 9.5 मिलियन लोग इसका शिकार बनेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, निर्माण कार्य एवं कंप्यूटर डाटा जो आज मात्र एक फीसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण हैं, वर्ष 2040 तक ये 14 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमशः 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं यह इसलिए है, क्योंकि हम एक भोगवादी सभ्यता का बडा हिस्सा बन गए हैं। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमें यहां प्रकृति और विज्ञान के नियमों को समझने का समय है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। अब जो चर्चा का सबसे बडा विषय होना चाहिए वह यह कि हम अपनी जीवनशैली को ढेर सारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से न देखें। संसाधनों का आवश्यकता एवं सुविधा भर उपयोग एक तरफ जहां हमें लंबा जीवन दे सकता है वहीं प्रकृति और पृथ्वी को भी विचलित नहीं करेगा। यह पूरी तरह सच है कि हमारी तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने हमें ऐसे मो ? पर पहुंचा दिया है जहां से आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीने के तौर–तरीकों में सुविधाओं से ज्यादा साधनों के उन तरीकों को अपनाएं जो सततता प्रदान कर सकते हैं।

दो चरणो में रोड शो - चुनाव अभियान शुरु

अमित शाह का अहमदाबाद में रोड शो : चुनाव अभियान शुरु

गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अमित शाह ने चुनावी अभियान शुरु किया : रोड शो में भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगे

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अमित शाह ने आज से अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया। पार्टी के स्थापना दिन के अवसर पर चुनाव अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने आज दो चरणो मे रोड शो आयोजित किया। जिसमें पहला चरण वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया। जिसकी शुरुआत सुबह ९ बजे हुई। प्रथम चरण के रोड शो का समापन हवेली मंदिर पर हुआ। दुसरी ओर दुसरे चरणे के रोड शो की शुरुआत राणीप में शांम ५.३० बजे हुई। यह रोड शो अहमदाबाद में राणीप से निर्णयनगर गरनाला होकर चांदलोडिया और अन्य विस्तार में पहुंचा। देवभूमि रोड पर दुसरे चरण के रोड शो की पूर्णाहुति हुई। अमित शाह अब आक्रमक चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह रोड शो के बाद घाटलोडिया विधानसभा के बोपर इलाके में अलग अलग सोसायटी के लोगो से भी मिले। भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के गांधीनगर से उम्मीदवार अमित शाह ने शनिवार को यहां रोडशो किया जहां उन्होंने लोगों से ''पूरा कश्मीर हमारा है'' के नारे लगाने के लिए कहा। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में शाह की आलोचना की थी कि वह कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद ३७० को हटाने का दिवास्वप्न देख रहे हैं। इसके बाद शाह ने कश्मीर के नारे लगवाए। शाह ने पार्टी के ३९वें स्थापना दिवस पर अपने चुनाव प्रचार अभियान के तौर पर शहर में रोडशो किया। अहमदाबाद के सरखेज इलाके से सुबह करीब नौ बजे शुरू हुए रोडशो से पहले शाह ने जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। शाह ने वहां मौजूद लोगों से जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है के नारे लगाने के लिए कहा। शाह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी के साथ एक खुले वाहन में रोडशो शुरू किया। रोडशो अहमदाबाद शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरा जो गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। वेजलपुर, आनंदनगर, जीवराज पार्क, मानसी क्रॉस रोड इलाकों के अलावा रोडशो मुस्लिम बहुल जुहापुरा इलाके से भी होकर गुजरा। यह दोपहर करीब एक बजे वस्त्रपुर इलाके में हवेली पर खत्म हुआ। करीब दस किलोमीटर का रोडशो ग्रामीण के साथ-साथ पॉश इलाकों से होकर गुजरा जहां झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद लोग शाह का स्वागत करने बाहर निकले। भाजपा प्रमुख ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। गुजरात से राज्यसभा सदस्य शाह के शनिवार रात को उनके निर्वाचन क्षेत्र के बोपल इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने की उम्मीद है। उन्हें गांधीनगर सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के स्थान पर उतारा गया है। आडवाणी साल १९९८ से इस सीट पर जीतते रहे हैं। यह शाह का पहला लोकसभा चुनाव है। भाजपा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की मौजूदगी में गत शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया था।

गुजरात में पांच उम्मीदवारों को छोड़कर सारे करोड़पति

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
गुजरात में २६ लोकसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ जमा किए गए शपथ पत्रों से यह पता चला है। एक करोड़ रुपए से कम आय वाले पांच में से चार उम्मीदवार जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं। दोनों दलों के सबसे अमीर उम्मीदवारों में कांग्रेस के मेहसाणा से उम्मीदवार अम्बालाल पटेल शामिल हैं, जिनकी घोषित पूंजी ६९.९ करोड़ रुपए है। बीजेपी उम्मीदवार और नवसारी से मौजूदा सांसद चंद्रकांत पटेल की घोषित पूंजी ४४.६ करोड़ रुपए हैं। जामनगर से बीजेपी सांसद पूनम मादम की घोषित पूंजी ४२.७ करोड़ रुपए है। वह इस बार भी जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं। मेहसाणा से बीजेपी की उम्मीदवार शारदाबेन पटेल के पास ४४ करोड़ रुपए की पूंजी है। रमेश धाडुक ने ३५.७५ करोड़ रुपए की पूंजी की घोषणा की है। कांग्रेस के तीन और बीजेपी के दो उम्मीदवारों की घोषित पूंजी एक करोड़ रुपए से कम है। अमीर उम्मीदवारों में कांग्रेस के मेहसाणा से उम्मीदवार अम्बालाल पटेल , जिनकी घोषित पूंजी ६९.९ करोड़ हैभरुच से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा की घोषित पूंजी ६८.३५ लाख रुपए, कांग्रेस उम्मीदवार शेरखान पठान की घोषित पूंजी ३३.४ लाख रुपए, कच्छ से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश माहेश्वरी की कुल पूंजी ३८.१३ लाख रुपए, बीजेपी उम्मीदवार गीताबेन राठवा की घोषित पूंजी ८६.३ लाख रुपए और कांग्रेस उम्मीदवार जीतू चौधरी की कुल घोषित पूंजी ६६.१ लाख रुपए है। कुल पूंजी में उम्मीदवारों, उनके जीवनसाथियों और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति शामिल होती है। गुजरात की २६ लोकसभा सीटों के लिए ५७३ उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां २३ अप्रैल को चुनाव होंगे।

प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकले थी

प्रियंका के चुनाव लड़ने पर निर्णय नहीं हुआ हैं : शुक्ला

प्रियंका के नेतृत्व में पार्टी अच्छा करेगी और संगठन मजबूत होने के बाद २०२२ के विधानसभा चुनाव में स्वीप करेगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,
प्रियंका गांधी के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से जुड़ी हालिया अटकलों की पृष्ठभूमि में गांधी परिवार के विश्वस्त और प्रियंका के बेहद नजद़ीकी लोगों में शुमार वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने रविवार को कहा कि कांग्रेस महासचिव के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने यह दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा करेगी और संगठन मजबूत होने के बाद २०२२ के विधानसभा चुनाव में स्वीप करेगी। प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की हालिया अटकलों पर शुक्ला ने कहा, एक सवाल के जवाब में प्रियंका जी ने एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर बातें की गई थीं। उनके चुनाव लड़ने पर अभी कुछ तय नहीं है। कोई निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल, कुछ हफ्ते पहले चुनाव प्रचार के दौरान जब एक व्यक्तिने प्रियंका से चुनाव लड़ने के बारे में कहा तो पलटकर उन्होंने सवाल किया, क्या मैं वाराणसी से लडूं ? उनकी इस टिप्पणी के बाद ये अटकलें शुरू हो गईं कि प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि इस बारे में खुद प्रियंका को निर्णय करना है। शुक्ला ने प्रियंका के प्रचार अभियान के असर के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''वह जहां जा रही है उन्हें जनता से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारी दिक्कत यह है कि पिछले २० वर्षों में हमारा संगठन काफी कमजोर हो गया है। इसे दोबारा खड़ा करना है। फिर प्रियंका जी का नेतृत्व होगा और हम २०२२ में स्वीप करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी के नेतृत्व का लाभ हमें लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। हम इस चुनाव में अच्छा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शुक्ला ने यह दावा भी किया कि इस बार जनता के बीच ''मोदी ब्रांड'' नहीं चलेगा और विपक्ष को सामूहिक रूप से बहुमत हासिल होगा।उन्होंने यह दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका के नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा करेगी और संगठन मजबूत होने के बाद २०२२ के विधानसभा चुनाव में स्वीप करेगी। प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की हालिया अटकलों पर शुक्ला ने कहा, एक सवाल के जवाब में प्रियंका जी ने एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर बातें की गई थीं। उनके चुनाव लड़ने पर अभी कुछ तय नहीं है। कोई निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल, कुछ हफ्ते पहले चुनाव प्रचार के दौरान जब एक व्यक्ति ने प्रियंका से चुनाव लड़ने के बारे में कहा तो पलटकर उन्होंने सवाल किया, क्या मैं वाराणसी से लडूं ? उनकी इस टिप्पणी के बाद ये अटकलें शुरू हो गईं कि प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। यह पूछे जाने पर कि भाजपा के चुनावी विमर्श की काट क्या है तो उन्होंने कहा, वो हिंदू-मुसलमान और पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। उनके एजेंडे की यही काट है कि हम आम आदमी की बात कर रहे हैं।

बडौदा में निर्मला सीतारामन का संबोधन

फीर एकबार मोदी सरकार का सूत्र यथार्थ साबित होगा

भाजपा को जीत दिलाने के लिए देशभर में कार्यकर और समर्थक अब अथाग परिश्रम कर रहे है : सीतारामन

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
केन्द्रिय रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने भाजपा के ३९ वें स्थापना दिवस के अवसर पर बडौदा में एक कार्यक्रम में हाजरी दी। इस अवसर पर निर्मला सीतारामन ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार के सूत्र को यथार्थ करने के लिए केन्द्रिय नेतृत्व, स्थानिय नेतृत्व, कार्यकर्ता और समर्थक अथाग परिश्रम कर रहे है। देशभर में कार्यकर्ता और केन्द्रिय नेतृत्व परिश्रम में लगा हुआ है। निर्मला सीतारामन ने बताया कि साल २०१९ के चुनाव देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पुनरावर्तन करने के लिए चुनाव है। उन्होंने कहा कि साल २०१४ लोकसभा चुनाव के दौरान वे बडौदा आई थी। साल २०१९ के लोकसभा चुनाव में भी फिर एकबार बडौदा में उपस्थित है। २०१४ की तरह ही २०१९ के चुनाव देश के लिए खूब महत्वपूर्ण है। २०१४ के चुनाव प्रजाविरोधी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव थे। साल २०१९ के चुनाव देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। रोजगार, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा सभी क्षेत्रो में देश ने पिछले पांच सालो में मोदी का निर्णायक नेतृत्व देखा है। पिछले पांच वर्षो में देश में जो कामो की निव रखी गई है उन्हे पूर्णता के किनारे पर ले जाने के लिए फिर एकबार मोदी का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। साल २०१४ से २०१९ के दौरान बडौदा में केन्द्र सरकार की ओर से किये गए कामो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बडौदा को देश की प्रथम युनिवर्सिटी मिली है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन ट्रेनिंग सेन्टर भी बडौडा में बन रहा है। देशभर में कार्यकर्ता और केन्द्रिय नेतृत्व परिश्रम में लगा हुआ है। निर्मला सीतारामन ने बताया कि साल २०१९ के चुनाव देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पुनरावर्तन करने के लिए चुनाव है। उन्होंने कहा कि साल २०१४ लोकसभा चुनाव के दौरान वे बडौदा आई थी। साल २०१९ के लोकसभा चुनाव में भी फिर एकबार बडौदा में उपस्थित है। २०१४ की तरह ही २०१९ के चुनाव देश के लिए खूब महत्वपूर्ण है। २०१४ के चुनाव प्रजाविरोधी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव थे। साल २०१९ के चुनाव देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। साल २०१९ के चुनाव देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। रोजगार, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा सभी क्षेत्रो में देश ने पिछले पांच सालो में मोदी का निर्णायक नेतृत्व देखा है। पिछले पांच वर्षो में देश में जो कामो की निव रखी गई है उन्हे पूर्णता के किनारे पर ले जाने के लिए फिर एकबार मोदी का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। साल २०१४ से २०१९ के दौरान बडौदा में केन्द्र सरकार की ओर से किये गए कामो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बडौदा को देश की प्रथम युनिवर्सिटी मिली है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन ट्रेनिंग सेन्टर भी बडौडा में बन रहा है। देशभर में कार्यकर्ता और केन्द्रिय नेतृत्व परिश्रम में लगा हुआ है।रोजगार, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा सभी क्षेत्रो में देश ने पिछले पांच सालो में मोदी का निर्णायक नेतृत्व देखा है।बडौदा-मुंबई एक्सप्रेस वे, सेन्ट्रल कन्टेनर डीपो जैसी सुविधाएं बडौदा में स्थापित हुई है। देश का दुसरा ग्रीन एयरपोर्ट भी बडौदा में हुआ है। फ्रेट कोरिडोर एग्रीकेल्चर सेन्टर की शुरुआत बडौदा में हुई है।

स्टार प्रचारको में स्मृति इरानी भी शामिल

गुजरात में मोदी और शाह समेत ४० प्रचारक उतरेंगे

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
गुजरात में २६ लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित साथ के साथ साथ ४० स्टार प्रचारको की फौज उतारेगी। इन स्टार प्रचारको में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय मंत्री उमा भारती, केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी, केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, गुजरात के प्रभारी व महामंत्री भूपेन्द्र यादव, लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर शामिल है। संगठन महामंत्री रामला, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी.सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू दलसाणिया पर भी रहेगी। इन स्टार प्रचारको की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यंत्री योगी, आदित्यनाथ तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस शामिल है। इसके साथ साथ मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी चुनाव प्रचार करेगी। पार्टी ने गुजरात से मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी, केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य के चार मंत्री आर.सी. फलदु, भूपेन्द्र चुडास्मा, गणपत वसावा व कुंवरजी बावलिया, वासण आहिर, राज्यसभा सांसद शंभूनाथ टुंडिया, पूर्व स्पीकर रमण वोरा, गुजरात भाजपा के उपाध्यक्ष आई.के. जाडेजा, पूर्व मंत्री आत्माराम परमार, पूर्व विधायक हीरा सोलंकी और रणछोड़ रबारी शामिल है। गुजरात में प्रचार के लिए बॉलिवुड नेता भी आएंगे। इनमें पूर्व जमाने की अभिनेत्री व मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी, मौजूदा सांसद व एक्टर परेश रावल, गुजराती फिल्मों के अभिनेता व विधायक हितु कनोडिया, मनोज जोशी भी शामिल है। जोशी का नाम पूर्व सीट से उम्मीदवार के रूप में लिया जा रहा था।

किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा था

जूनागढ़ के लूशाला गांव में किसान की खुदकुशी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,
गुजरात के जूनागढ़ जिले के लूशाला गांव में आर्थिक संकट से जूझ रहे एक किसान ने अपने घर में फंदा लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। वनथाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि मृतक दिलीप तताभिया के पास अपने दो भाइयों के साथ साझे की ०.४ हेक्टेयर जमीन थी। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिये वह बिजली मिस्त्री के तौर पर भी काम करता था। यहां से करीब ३०० किलोमीटर दूर तताभिया ने शुक्रवार रात लूशाला गांव स्थित अपने आवास पर खुदकुशी कर ली। अधिकारियों ने बताया कि मृतक के एक किशोर बेटा है। अधिकारियों ने कहा, तताभिया पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था।वनथाली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि मृतक दिलीप तताभिया के पास अपने दो भाइयों के साथ साझे की ०.४ हेक्टेयर जमीन थी। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिये वह बिजली मिस्त्री के तौर पर भी काम करता था। अधिकारियों ने कहा, तताभिया पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। उसकी पत्नी का करीब १५ साल पहले निधन हो गया था। उसके दो छोटे भाई विवाह के बाद अलग रहते थे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।

साड़ी में भी बेहद सेक्सी लग रही हैं आलिया भट्ट

आलिया अपकमिंग फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी

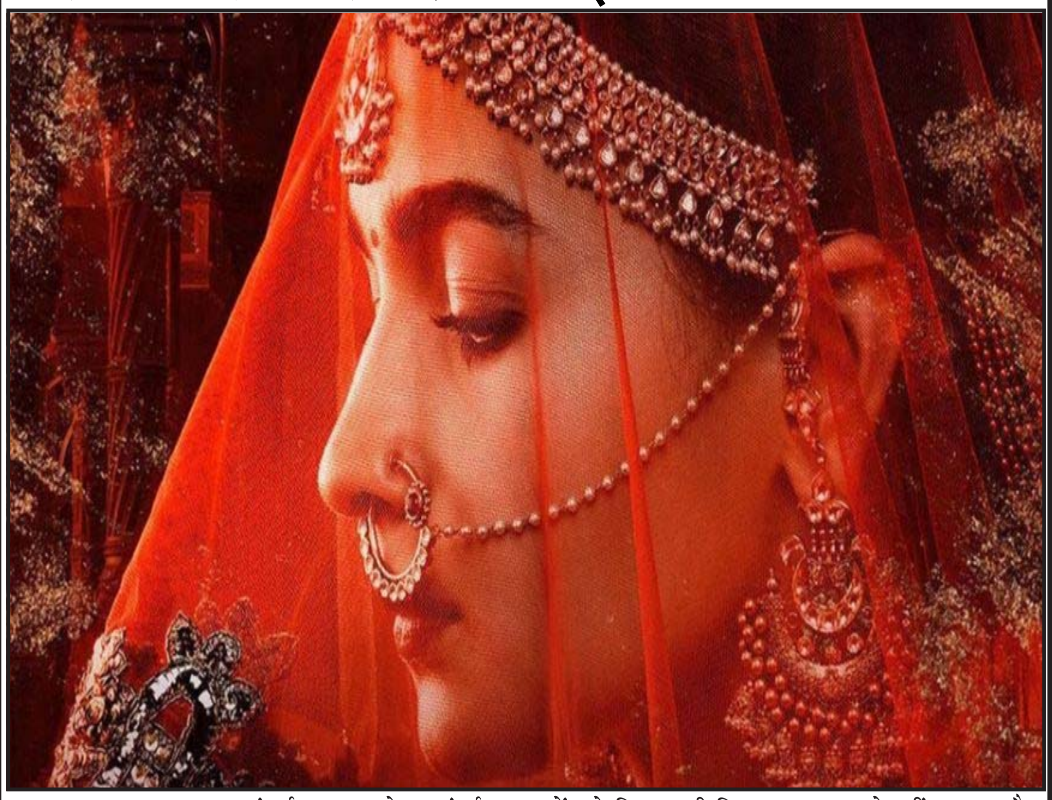

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,
बीटाउन की फैशनिस्टा गर्ल आलिया भट्ट एक बार फिर बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सब्यसाची की साड़ी में फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वह एलिगेंट लगने के साथ ही सेक्सी भी लग रही हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने कॉमेंट के जरिए ही आलिया को आई लव यू तक कह डाला। आलिया भट्ट इन फोटोज में ग्रीन कलर की स्टाइलिश साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं। यह साड़ी आम साड़ी से हटकर है। सब्यसाची की इस साड़ी के साथ आलिया ने ऑफ शोल्डर ब्लाज पहना है जो उन्हें सेक्सी लुक दे रहा है। ग्रीन और येलो डिजाइन के कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी को फ्रिल्स में डिजाइन किया गया है। पारंपरिक साड़ी की तरह इसमें पल्ला है जो आलिया के एक शोल्डर को कवर कर रहा है। इसके अलावा उनका एक शोल्डर ओपन है और पीछे बैकलेस लुक है जिससे साड़ी में भी आलिया का हॉट अवतार नजर आ रहा है। इस साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन डैंगलर्स पहने हैं और बालों को लूज पोनी में बांधा है। आगे से बाल स्ट्रेट और पीछे से उन्हें वेवी लुक दिया गया है। यह साड़ी आलिया ने किस इवेंट के लिए पहनी फिलहाल यह सामने नहीं आ सका है। जिनमें वह एलिगेंट लगने के साथ ही सेक्सी भी लग रही हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने कॉमेंट के जरिए ही आलिया को आई लव यू तक कह डाला। आलिया भट्ट इन फोटोज में ग्रीन कलर की स्टाइलिश साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं। यह साड़ी आम साड़ी से हटकर है। सब्यसाची की इस साड़ी के साथ आलिया ने ऑफ शोल्डर ब्लाज पहना है जो उन्हें सेक्सी लुक दे रहा है। ग्रीन और येलो डिजाइन के कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी को फ्रिल्स में डिजाइन किया गया है। पारंपरिक साड़ी की तरह इसमें पल्ला है जो आलिया के एक शोल्डर को कवर कर रहा है। इसके अलावा उनका एक शोल्डर ओपन है और पीछे बैकलेस लुक है जिससे साड़ी में भी आलिया का हॉट अवतार नजर आ रहा है। इस साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन डैंगलर्स पहने हैं और बालों को लूज पोनी में बांधा है। वैसे आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं, जिसमें उनकी जोड़ी एक बार फिर वरुण धवन के साथ जमी है। फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी अहम रोल में हैं। करण जौहर के प्रॉडक्शन में बनी यह मूवी १७ अप्रैल को रिलीज होगी।

आलिया भट्ट फोटोज में ग्रीन कलर की स्टाइलिश साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं : यह साड़ी आम साड़ी से हटकर

सुरक्षा के विषय पर देश किसी तरह की नरमी नहीं रखेगा

संकल्प पत्र में किसानों, युवा और महिलाओं पर होगा फोकस

बीजेपी को लोगों सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव भी शामिल है

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

बीजेपी चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। किसानों के कल्याण के संदर्भ में बीजेपी को लोगों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव भी शामिल है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बीजेपी का संकल्प पत्र सोमवार को जारी किया जाना प्रस्तावित है। पार्टी इसके साथ पिछले पांच वर्षों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें किसानों पर जोर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख किया और जोर दिया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर देश किसी तरह की नरमी नहीं रखेगा। किसान और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का खाका भी पेश किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करने संबंधी न्याय योजना के वादे के मद्देनजर बीजेपी अपने संकल्प पत्र को ज्यादा धारदार और लुभावना बनाकर पेश करना चाहती है। पार्टी इसके साथ पिछले पांच वर्षों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें किसानों पर जोर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख किया और जोर दिया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर देश किसी तरह की नरमी नहीं रखेगा।इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को १० प्रतिशत आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को व्यापक बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हो सकती है। किसान कल्याण के संबंध में बीजेपी को लोगों से बड़े पैमाने पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव प्रमुख है। पार्टी को किसानों के लिए कृषक भविष्य निधि योजना का सुझाव भी प्राप्त हुआ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में किसानों के मन की बात को भारत के मन की बात में प्रमुख स्थान देना चाहती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान होगा। पार्टी को लोगों से इस संबंध में काफी सुझाव भी प्राप्त हुए हैं जिसमें मंत्रिपरिषद में महिलाओं के लिए कम से कम १५ प्रतिशत आरक्षण, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा संबंधी आयोयों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव शामिल है।

राज ठाकरे की उर्मिला को सलाह

चुनाव के बाद गायब न हो जाना : राज ठाकरे

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाली फिल्म ऐक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक सलाह दी है। पिछले हफ्ते जब उर्मिला अपने पुराने दोस्त राज से मिलने उनके घर गई थीं तो राज ने उन्हें राजनीति में लंबी पारी खेलने का मंत्र दिया। राज ने उनसे कहा है कि चुनाव के बाद भी वह लोगों के लिए काम करती रहीं तो कांग्रेस और राजनीति में काफी आगे जाएंगी। उर्मिला कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनाव मैदान में उतरेंगी। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी होंगे।

राज ने अपना समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और एनसीपी को दे रखा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि एमएनएस की मदद से उर्मिला अपने क्षेत्र की मराठी आबादी को लुभाने में सफल हो सकेंगी। राज ने उर्मिला को इस बात का आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर मुंबई में उर्मिला के लिए ही प्रचार करेंगे। राज ने उर्मिला से कहा, चुनाव के बाद गायब न हो जाइएगा। लोगों के लिए काम करती रहिएगा और आप बहुत आगे जाएंगी।

लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी नारा

'अब होगा न्याय' कांग्रेस ने जारी किया चुनावी नारा

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नया नारा जारी कर दिया है। 'अब होगा न्याय' नारे को जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि देश में 'अन्याय' का माहौल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का प्रचार अभियान भी 'न्याय' के ईद गिर्द केन्द्रित होगा। यह शब्द न केवल पार्टी की प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी योजना को रेखांकित करता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को न्याय प्रदान करने की बात भी करता है। शर्मा ने आगे कहा कि इसका थीम सॉन्ग जावेद अख्तर ने लिखा है और निखिल आडवाणी ने इसके विडियो का निर्देशन किया है। शर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े-बडे कंटेनर ट्रक पर स्क्रीन लगाकर यह विडियो दिखाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े वादे न्याय के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी जन-जन तक पहुंचने के लिए पार्टी की युवा इकाई ने घर-घर पर्चे बांटने और नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत कर दी है।

मोदी पर आरएलडी प्रमुख सिंह के बिगड़े बोल

मां-बाप ने सच बोलना नहीं सिखाया :आरएलडी प्रमुख

मोदी साहब ने वादा किया था कि हर एक आदमी की जेब में १५ लाख पहुंचेगे : रैली में बोले अजित सिंह

(संपूर्ण समाचार सेवा) देवबंद,

यूपी के देवबंद में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के मुखिया अजित सिंह ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। एसपी, बीएसपी और लोकदल की संयुक्त रैली में पीएम पर निशाना साधते हुए सिंह ने यहां तक कह दिया कि मोदी के मां-बाप ने उनको सच बोलने की सलाह नहीं दी है। आरएलडी प्रमुख के इस बयान पर सियासी घमासान मचना तय है। रविवार को २५ साल बाद एसपी और बीएसपी के दोनों ही बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती साथ-साथ एक मंच पर दिखे। इस दौरान महागठबंधन में सहयोगी आरएलडी प्रमुख अजित सिंह भी मौजूद रहे। महागठबंधन में शामिल इन तीनों नेताओं ने बीजेपी खासकर पीएम नरेन्द्र मोदी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए अजित सिंह ने कहा, मोदी साहब ने वादा किया था कि हर एक आदमी की जेब में १५ लाख पहुंचेगे। देश का पीएम झूठ बोलता है ना ये झूठ नहीं बोलता, ये कभी सच नहीं बोलता। बच्चे को क्या सिखाते हैं आप कि बेटा सच बोला कर, मोदी के मां-बाप ने उसको सच बोलने की सलाह नहीं दी है। इस संयुक्त रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वेस्ट यूपी के मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस के झांसे में न आएं और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें। मोदी पर निशाना साधते हुए माया ने कहा, बीजेपी के छोटे-बड़े चौकीदार कुछ भी कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे दिन का वादा कर मोदी ने लोगों को गुमराह किया और सरकारी खजाने को लूटा दिया। आरएलडी प्रमुख के इस बयान पर सियासी घमासान मचना तय है। रविवार को २५ साल बाद एसपी और बीएसपी के दोनों ही बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती साथ-साथ एक मंच पर दिखे। इस दौरान महागठबंधन में सहयोगी आरएलडी प्रमुख अजित सिंह भी मौजूद रहे। महागठबंधन में शामिल इन तीनों नेताओं ने बीजेपी खासकर पीएम नरेन्द्र मोदी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए अजित सिंह ने कहा, मोदी साहब ने वादा किया था कि हर एक आदमी की जेब में १५ लाख पहुंचेगे। देश का पीएम झूठ बोलता है ना ये झूठ नहीं बोलता, ये कभी सच नहीं बोलता। उधर, अखिलेश ने लोकसभा चुनाव को इतिहास बनाने का चुनाव बताया। अखिलेश ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा, कहा कि यहां ऐसे भी नेता आए होंगे जो नफरत के अलावा कुछ नहीं बोले होंगे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, पहले हमारे बीच में चायवाला बनकर आ गए और हम लोगों ने अच्छे दिन, १५ लाख रुपये और करोड़ों नौकरियों का भरोसा कर लिया।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला की प्रतिक्रिया

हरियाणा, पंजाब में AAP के साथ गठबंधन पर कोई बात नहीं

दोनों राज्यों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द : सुरजेवाला

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि हरियाणा और पंजाब में आप या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के लिए उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही और वह इन दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्क के साथ गठबंधन को लेकर अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। शनिवार को आप के एक नेता ने कहा कि पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन तभी करेगी यदि राहुल गांधी की पार्टी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो। सुरजेवाला एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे जिसमें कांग्रेस ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान 'अब होगा न्याय' सामने रखा। उन्होंने कहा, आप सहित किसी भी पार्टी के साथ हरियाणा या पंजाब में गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम (दोनों राज्यों के लिए) अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी दिल्ली में क्क के साथ गठबंधन के बारे में अभी किसी निर्णय नहीं पहुंची है।' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुद्दे पर दिल्ली से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव और पार्टी की राष्ट्रीय राजधानी इकाई के प्रभारी पी सी चाको और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गठबंधन के लिए एक और पूर्व शर्त के तौर पर क्क ने कांग्रेस से कहा है कि वह दिल्ली के वास्ते पूर्ण राज्य के लिए अपने समर्थन की घोषणा करे। शनिवार को आप के एक नेता ने कहा कि पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन तभी करेगी यदि राहुल गांधी की पार्टी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो। शनिवार को आप के एक नेता ने कहा कि पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन तभी करेगी यदि राहुल गांधी की पार्टी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो। सुरजेवाला एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे जिसमें कांग्रेस ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान 'अब होगा न्याय' सामने रखा। उन्होंने कहा, आप सहित किसी भी पार्टी के साथ हरियाणा या पंजाब में गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम (दोनों राज्यों के लिए) अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेंगे।सुरजेवाला एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे जिसमें कांग्रेस ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान 'अब होगा न्याय' सामने रखा। उन्होंने कहा, आप सहित किसी भी पार्टी के साथ हरियाणा या पंजाब में गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम (दोनों राज्यों के लिए) अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी दिल्ली में क्क के साथ गठबंधन के बारे में अभी किसी निर्णय नहीं पहुंची है।' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुद्दे पर दिल्ली से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। क्क ने कांग्रेस को कथित रूप से कहा है कि वह चंडीगढ़ में उसे समर्थन करेगी यदि उसे हरियाणा में तीन सीटों पर चुनाव लड़ने दे जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव और करनाल शामिल हैं।

आचारसंहिता का भंग होगा तो, शिकायत दर्ज होगी

भाजपा के नेता मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा

दिलीप ठाकोर, विधायक मधु श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

भाजपा के कैबिनेट मंत्री दिलीप ठाकोर और विधायक मधु श्रीवास्तव के विवादास्पद बयान को लेकर लोकसभा चुनाव में राजनीति गर्मा गई है और अब चुनाव आयोग यह दोनों नेताओं के केस में रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यदि जांच में चुनाव आचारसंहिता भंग होने का मामला सामने आयेगा तो, चुनाव आयोग द्वारा पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई जाए ऐसी संभावना रही है। जिसे लेकर फिलहाल तो, भाजपा बैकफुट पर आ गई है। हालांकि, दूसरी तरफ, चुनाव आयोग भी कांग्रेस द्वारा यह दोनों मामलों में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत करके कार्रवाई करने की मांग के संदर्भ में अब चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाती है कि नहीं इस पर सभी की नजर है। चुनाव के समय विवादित बयान देकर बिगड़े बोल बोलने के मामले में पाटण में गत ३ अप्रैल को भाजपा के उम्मीदवार भरतसिंह डाभी के फॉर्म भरने से पहले आयोजित की गई जनसभा में कैबिनेट मंत्री दिलीप ठाकोर द्वारा खुले मंच से सर्जिकल स्ट्राइक के सूबत मांगते कांग्रेस के सीनियरों को बम के साथ बांधकर फेंक दो ऐसा विवादास्पद बयान दिया। जिसे लेकर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। कैबिनेट मंत्री द्वारा खुद इस प्रकार के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। निरीक्षक टीम द्वारा चुनाव विभाग से यह निवेदन मामले में विडियो भी मांगा गया। भाजपा बैकफुट पर आ गई है। हालांकि, दूसरी तरफ, चुनाव आयोग भी कांग्रेस द्वारा यह दोनों मामलों में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत करके कार्रवाई करने की मांग के संदर्भ में अब चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाती है कि नहीं इस पर सभी की नजर है। चुनाव के समय विवादित बयान देकर बिगड़े बोल बोलने के मामले में पाटण में गत ३ अप्रैल को भाजपा के उम्मीदवार भरतसिंह डाभी के फॉर्म भरने से पहले आयोजित की गई जनसभा में कैबिनेट मंत्री दिलीप ठाकोर द्वारा खुले मंच से सर्जिकल स्ट्राइक के सूबत मांगते कांग्रेस के सीनियरों को बम के साथ बांधकर फेंक दो ऐसा विवादास्पद बयान दिया। जिसे लेकर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अब चुनाव अधिकारियों द्वारा यह निवेदन के विडियो सहित स्थल पर मौजूद रहे सरकारी अधिकारियों, शब्द उच्चारण के अर्थ सहित की जांच करके पूरा रिपोर्ट तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी को सूचना द दी गई है। हालांकि यह जांच में कैबिनेट मंत्री दिलीप ठाकोर के बयान से चुनावी आचारसंहिता का भंग होने का स्पष्ट होगा तो चुनाव आयोग द्वारा धारा-१७१ के अनुसार शिकायत उनके विरूद्ध दर्ज कराई जाए ऐसी संभावना है यदि चुनाव आचारसंहिता का भंग नहीं होता तो यह मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी यह चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया।

बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को दरकिनार किया

बड़े नेताओं को दरकिनार कर नौ सांसदों का टिकट कटा

प्रभावशाली लोगों के विरोध और किसी भी नाराजगी की चिंता किए बगैर बीजेपी ने यह कदम उठाया हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

बीजेपी ने शनिवार को ९ और सांसदों का टिकट काट दिया। प्रभावशाली लोगों के विरोध और किसी भी नाराजगी की चिंता किए बगैर बीजेपी ने यह कदम उठाया। बीजेपी ने एक बेहद रूचिकर चुनाव करते हुए जयपुर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीया कुमारी को राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे करते हुए बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके संबंधों को भी नजरअंदाज कर दिया। यह दूसरा मौका है, जब बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है, जो वसुंधरा राजे को असहज कर सकता है। इससे पहले बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को नागौर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, बेनीवाल वसुंधरा से विरोध के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे। बेनीवाल बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जहां दीया कुमारी की उम्मीदवारी राजसंमद लोकसभा सीट से वर्तमान उम्मीदवार हरिओम सिंह राठौर के खराब स्वास्थ्य के चलते तय की गई है, वहीं बांदा से स्थानीय विरोध के बावजूद सांसद भैरो प्रसाद मिश्रा की जगह आरके पटेल को टिकट दिया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इस सीट से जतिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए एसपी ने श्यामा प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है। मिश्रा ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ धरना देने की बात भी कही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद गुप्ता इससे पहले इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद थे। जब उन्हें लगा कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है तो उन्होंने एसपी का दामन थाम लिया। झांसी की लोकसभा सीट से उमा भारती की तरफ से स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने का ऐलान करने के बाद बैद्यनाथ ग्रुप के अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बैद्यनाथ ग्रुप आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा नाम है। इससे पहले बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को नागौर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, बेनीवाल वसुंधरा से विरोध के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे। बेनीवाल बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जहां दीया कुमारी की उम्मीदवारी राजसंमद लोकसभा सीट से वर्तमान उम्मीदवार हरिओम सिंह राठौर के खराब स्वास्थ्य के चलते तय की गई है, वहीं बांदा से स्थानीय विरोध के बावजूद सांसद भैरो प्रसाद मिश्रा की जगह आरके पटेल को टिकट दिया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इस सीट से जतिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए एसपी ने श्यामा प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है। मिश्रा ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ धरना देने की बात भी कही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।अनुराग शर्मा के पिता बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। रांची सीट से पार्टी के सीनियर नेता राम तहल चौधरी को संजय सेठ के लिए सीट छोड़नी पड़ी। चौधरी इलाके के बड़े कुर्मी नेता हैं, जो इस साल ७७ वर्ष के हो गए हैं। चौधरी ने बेहद आसानी से यह सीट जीती थी। झारखंड के पूर्व मंत्री और कोडरमा से वर्तमान सांसद रवींद्र रॉय की जगह आरजेडी से पार्टी में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर से सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर को इस बार मुरैना से टिकट दिया गया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH